

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शो,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
इरला चैंक अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन ।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 01 मार्च, 2008

विषय- अधिवक्ता कल्याण कोष में धनराशि का अन्तरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में वकालतनामों पर लगने वाले रुपये 10/- के अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्पों को उत्तराखण्ड के कोषागारों द्वारा की गई बिक्री से दिनांक 31-12-2007 तक अर्जित एवं जमा कुल धनराशि रुपये 6964965/- (उनहत्तर लाख चौसठ हजार नौ सौ पैसठ रुपये मात्र) में से पूर्व में अधिवक्ता कल्याण कोष कमेटी में शासनादेश संख्या-32एक(1)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2005, दिनांक 28.02.2005 द्वारा अन्तरित धनराशि रु० 22,00,000/-, शासनादेश संख्या-200-एक(1)/XXXVI(1)/2006, दिनांक 28.03.2006 द्वारा अन्तरित धनराशि रु० 10,00,000/- एवं शासनादेश संख्या-76-दो(1)/XXXVI(1)(2)/2006-200-एक(1)/04, दिनांक 15.03.2007 द्वारा अन्तरित धनराशि रुपये 20,00,000/- अर्थात् कुल जमा धनराशि रु० 52,00,000/- को घटाते हुए शेष धनराशि रु० 17,64,965/- (सत्रह लाख चौसठ हजार नौ सौ पैसठ रुपये मात्र) को उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण कोष कमेटी के नाम से सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक में सदस्य सचिव के नाम से खुले खाता संख्या-01100215080 में अन्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त धनराशि का आहरण वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जायेगा एवं इस धनराशि का आहरण करके सदस्य सचिव, अधिवक्ता कल्याणकारी कोष कमेटी के नाम सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खुले खाता संख्या-01100215080 में जमा की जायेगी ।
 - (2) उक्त धनराशि का बैंक से आहरण एवं व्यय अधिवक्ता कल्याण कोष की नियमावली की व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा । उक्त कोष से भिन्न प्रयोजनों हेतु इसका व्यय नहीं किया जायेगा ।
 - (3) बैंक में रखी गयी धनराशि के लेखे का उचित रख-रखाव भी किया जायेगा ।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-800-अन्य व्यय-08-अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण-00-42-अन्य व्यय" के नामों डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1409/XXVII(s)/2007, दिनांक 26-02-2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या : 103-दो(1)/XXXVI(1)(2)/2007-200-एक(1)/04-तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, औबेराय भवन, माजरा, देहरादून ।
- 2- महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
- 3- सदस्य सचिव, अधिवक्ता कल्याणकारी कोष कमेटी, सचिवालय, देहरादून ।
- 4- अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बार कौंसिल, मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 6- वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(क०पी०पाटनी)

अनु सचिव ।